शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 33 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 10 – 17 अगस्त 2026 मूल्य पांच रूपये

2047 तक विकसित भारत, क्या आसान होगी राह?

शिमला/शैल। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का बड़ा लक्ष्य सामने रखा, लेकिन इस लक्ष्य के साथ सरकार ने देश के सामने आत्मनिर्भरता, रोजगार, तकनीक, रक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की कठिन चुनौतियां भी रख दी हैं। करीब डेढ़ घंटे से अधिक लंबे संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई और आने वाले 5 से 7 वर्षों के लिए 'शक्ति की सप्त धारा' के जरिए भारत की आर्थिक और रणनीतिक दिशा तय करने का संकेत दिया।

प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि आने वाले दौर में भारत केवल विदेशी कंपनियों के लिए बड़ा बाजार नहीं रह सकता। देश को डिजाइन से लेकर उत्पादन और छोटे पुर्जो से लेकर तैयार उत्पाद तक पूरी वैल्यू चेन अपने यहां विकसित करनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग को पहली प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने 'जीरो डिफेक्ट' और गुणवत्ता को वैश्विक पहचान बनाने की जरूरत बताई। इसका सीधा संदेश घरेलू उद्योग और एमएसएमई के लिए है कि अब संरक्षण से ज्यादा प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता पर टिकना होगा।

सेमीकंडक्टर को लेकर प्रधानमंत्री ने दावा किया कि तीन प्लांट शुरू हो चुके हैं और आने वाले वर्षों में 5 से 8 और प्लांट शुरू किए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा सुरक्षा को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया गया। 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य सामने रखकर सरकार ने संकेत दिया कि एआई, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और आधुनिक उद्योगों की बढ़ती बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी।

प्रधानमंत्री के भाषण में वैश्विक व्यापार को लेकर भी आक्रामक रणनीति दिखाई दी। करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने एमएसएमई, किसानों और उद्योगों से वैश्विक बाजार में उतरने का आहवान किया। लेकिन इसके साथ गुणवत्ता और वैश्विक मानकों को पूरा करने की चुनौती भी सामने रखी। यानी भारतीय उत्पादों के लिए बाजार खुलने के साथ विदेशी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार भी खुलेंगे। ऐसे में घरेलू उद्योगों की वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी परीक्षा होगी।

कृषि को दूसरी 'शक्ति धारा' बताते हुए प्रधानमंत्री ने खेत से सीधे वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने की बात कही। रसायन मुक्त खेती और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। इससे किसानों के लिए निर्यात के अवसर बढ़ाने की कोशिश दिखाई देती है, लेकिन इसके लिए भंडारण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता प्रमाणन, परिवहन और निर्यात ढांचे को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी होगा।

युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने अगले एक साल में एक करोड़ युवाओं को एआई स्किल देने की घोषणा की। देश में ढाई लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप और एक लाख करोड़ रुपये के इनोवेशन फंड का उल्लेख करते हुए उन्होंने युवाओं को नई अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने का आहवान किया। शिक्षा, रिसर्च और रोजगार के बीच मौजूद दूरी को पाटना अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी।

महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर प्रधानमंत्री ने तीन करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य पूरा होने और छह करोड़ लखपति दीदियां बनाने का नया लक्ष्य रखा। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के लिए महिला आरक्षण लागू करने की अपील की। यह घोषणा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे महिला प्रतिनिधित्व का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री का रुख और ज्यादा सख्त रहा। ड्रोन, काउंटर-ड्रोन, हाइपरसोनिक तकनीक और साइबर सुरक्षा में भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में ले जाने की बात कही गई। उन्होंने 'मिशन सुदर्शन चक्र' का उल्लेख करते हुए कहा कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है और खतरे केवल सीमा तक सीमित नहीं हैं। रक्षा निर्यात बढ़ने और करीब 100 देशों तक भारतीय हथियार पहुंचने का दावा भी किया गया।

भाषण का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' को लेकर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र के साथ राज्यों और स्थानीय

शेष पृष्ठ 8 पर.....

घोषणाओं से आगे कब बढ़ेगा रोजगार का मुद्दा?

शिमला/शैल। हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की जरूरत लगातार बनी हुई है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने घुमारवीं में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं। इनमें जल शक्ति विभाग के 4,000 पद भरने के साथ आने वाले समय में 4,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा प्रमुख है। सवाल यह है कि इन घोषणाओं का लाभ युवाओं को कब तक मिलेगा।

सरकार की ओर से बताया गया कि अब तक 6,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं और 4,000 और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। लेकिन प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा लंबे समय से सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में नई भर्तियों की घोषणा के साथ उनकी नजर अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होने और नियुक्तियां मिलने पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है। घुमारवीं में राजकीय महाविद्यालय में एमबीए, एमसीए और एमटीए की कक्षाएं शुरू करने तथा घंडावली कॉलेज में बीबीए और बीसीए की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा भी की गई। इन पाठयक्रमों से युवाओं को उच्च शिक्षा के नए विकल्प मिलेंगे, लेकिन शिक्षा के बाद रोजगार की गारंटी अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

सरकार प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रोजगार का आधार बनाने की बात भी कर रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्राकृतिक खेती से हल्दी की खेती करने वाला किसान एक बीघा जमीन से सालाना एक लाख रुपये तक कमा सकता है। इसके अलावा ई-टैक्सियों और बसों के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने का दावा किया गया है।

लेकिन हिमाचल के युवाओं की सबसे बड़ी मांग नियमित और स्थायी रोजगार की है। आउटसोर्स और अस्थायी रोजगार के साथ युवाओं को लंबे समय तक भविष्य की सुरक्षा नहीं मिलती। सरकार ने खुद कई मौकों पर आउटसोर्स और मल्टी-टास्क कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर नीति बनाने की बात कही है। ऐसे में नई भर्तियों की घोषणाओं को जमीन पर उतारना सरकार के लिए बड़ी परीक्षा होगी।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के तहत प्रदेश में 156 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोलने और राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने की बात भी कही। शिक्षा में निवेश जरूरी है, लेकिन इसका वास्तविक असर तभी दिखाई देगा जब युवाओं को बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर भी मिलें।

घुमारवीं में वन मित्रों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने की घोषणा भी की गई। यह राहत जरूर है, लेकिन यह नियमित सरकारी नौकरी का विकल्प नहीं है। इसी तरह स्वरोजगार योजनाएं युवाओं को कुछ अवसर दे सकती हैं, लेकिन हर बेरोजगार युवा के लिए स्थायी समाधान नहीं बन सकती।

सरकार का दावा है कि वह रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रही है। दूसरी ओर युवाओं के सामने सवाल वही है घोषित पदों पर भर्ती कब शुरू होगी, परीक्षा कब होगी और नियुक्ति कब मिलेगी? हजारों युवाओं के लिए रोजगार केवल घोषणा नहीं, बल्कि समयबद्ध भर्ती और नियुक्ति का विषय है।

इसलिए सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती नई घोषणाएं करना नहीं, बल्कि पहले से घोषित भर्तियों को तय समय में पूरा करना है। 4,000 शिक्षकों और 4,000 जल शक्ति विभाग के पदों की भर्ती यदि पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी होती है तो इससे बेरोजगार युवाओं को वास्तविक राहत मिल सकती है। वरना रोजगार की घोषणाएं भी सरकारी घोषणाओं की लंबी सूची में जुड़कर रह जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने घुमारवीं को दी 466 करोड़ की 29 परियोजनाओं की सौगात

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के डढोल में 466 करोड़ रुपये

की लागत वाली 29 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इन परियोजनाओं में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, कौशल विकास, खेल, बिजली और पर्यटन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने 4.56 करोड़ रुपये की लागत से जल जीवन मिशन के तहत कोट – देहरा – हटवार उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना के रेट्रोफिटिंग कार्य का उद्घाटन किया। इसके अलावा 4.17 करोड़ रुपये से विभिन्न पेयजल योजनाओं के वितरण तंत्र में जंग लगी और जाम पाइपों को बदलने के कार्य को भी पूरा किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 9.38 करोड़ रुपये के सिविल अस्पताल घुमारवीं के आईपीडी ब्लॉक तथा 8.53 करोड़ रुपये के बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन किया गया। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में 6.45 करोड़ रुपये के कौशल विकास केंद्र, 2.52 करोड़ रुपये के पीएम श्री स्कूल भराड़ी भवन, 34.44 करोड़ रुपये के आईटीआई घुमारवीं विस्तार, 7.49 करोड़ रुपये के सीबीटी केंद्र और 12 करोड़ रुपये की कौशल अकादमी का शिलान्यास किया गया।

सड़क क्षेत्र में घुमारवीं विधानसभा की विभिन्न सड़कों की 72 करोड़ रुपये की मरम्मत सहित कई सड़कों के उन्नयन कार्यों का उद्घाटन किया गया। इनमें तरघेल – लदौर, रोपड़ी – मैर – हरितल्यांगर, तरघेल – कुरसाई – छतर – बरोटा तथा जुनाला – करलोटी – छत – बेरथिन सड़कें प्रमुख हैं।

क्षेत्र में खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 3.67 करोड़ रुपये के स्पोर्ट्स क्लब घुमारवीं तथा 3 – 3 करोड़ रुपये के स्पोर्ट्स स्टेडियम भराड़ी और मच्छवां का शिलान्यास किया गया। वहीं 29.43 करोड़ रुपये के राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे – बोर्डिंग स्कूल हटवाड़ भवन की आधारशिला भी रखी गई।

परिवहन और आधारभूत ढांचे के लिहाज से 103.31 करोड़ रुपये की लागत से भजवाणी गांव के समीप सतलुज नदी पर पुल तथा 93.52 करोड़ रुपये की औहर फेज – 2 वे – साइड एमेनिटीज परियोजना का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा औहर में एनएच – 154 पर 15 करोड़ रुपये की वाणिज्यिक सुविधाओं के विकास की आधारशिला रखी गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि घुमारवीं क्षेत्र में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिल्क समग्र – 2 योजना के तहत 2.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत 100 रेशम कीट पालन गृह स्वीकृत किए गए हैं और प्रत्येक के लिए 1.85 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने योजना के 10 लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए।

इन परियोजनाओं से घुमारवीं क्षेत्र में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, सड़क और खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

राज्यपाल ने लोक भवन में फहराया तिरंगा

शिमला/शैल। 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह लोक भवन में राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में मनाया गया। राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया

और पुलिस गार्ड की सलामी ली। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता भी मौजूद रहीं।

राज्यपाल ने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल तिरंगा फहराने का दिन नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति अपनी जिम्मेदारी दोहराने का अवसर है।

उन्होंने कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश भी आत्मनिर्भर हिमाचल और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव और सतत विकास के लिए मिलकर काम करने का आहवान किया। उन्होंने युवाओं से शिक्षा, खेल, नवाचार, उद्यमिता और जनसेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा।

उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से नशे से दूर रहने और 'नशा मुक्त हिमाचल' अभियान से जुड़ने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल की प्राकृतिक और पर्यावरणीय विरासत को सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर लोक भवन में बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय की स्मृति में एक पट्टिका का अनावरण भी किया। पट्टिका पर राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के छंद अंकित हैं। उन्होंने कहा कि यह गीत आज भी देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता है।

हिमालयी कृषि के लिए नया अनुसंधान रोडमैप तैयार

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी ने हिमाचल की कृषि, बागवानी और वानिकी को

मजबूत करने के लिए नया अनुसंधान एवं विस्तार रोडमैप तैयार किया है। इसमें जलवायु – सक्षम खेती, फसल विविधीकरण, किसान – केंद्रित तकनीक और डिजिटल विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है।

विश्वविद्यालय की अनुसंधान एवं विस्तार परिषद की बैठकों में रोडमैप पर चर्चा हुई। कुलपति प्रो. हरमिंदर सिंह बवेजा ने कहा कि अनुसंधान का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचना चाहिए। किसान की समस्या को अनुसंधान की प्राथमिकता बनाकर नई तकनीकों और नवाचारों को खेतों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय ने पिछले 10 महीनों में 33 हजार से अधिक किसानों तक प्रशिक्षण, रोग निदान, प्रदर्शन और अन्य विस्तार गतिविधियों के माध्यम से पहुंच बनाई है। इस दौरान 11.58 करोड़ रुपये के 29 अनुसंधान प्रोजेक्ट भी हासिल किए गए हैं।

भविष्य में जलवायु परिवर्तन, कीट – रोग, जल संरक्षण और नई फसलों पर अनुसंधान बढ़ाया जाएगा। एवोकाडो, कीवी, बेरीज, नट्स और ड्रैगन फ्रूट जैसी फसलों की संभावनाओं का भी अध्ययन होगा।

विश्वविद्यालय ने 'वेस्ट टू वेल्थ', बायोचार और पाइन ब्रिकेटिंग जैसी तकनीकों को बढ़ावा देने के साथ पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर भी ध्यान देने का फैसला किया है। डिजिटल माध्यमों और एआई आधारित तकनीकों के जरिए किसानों तक वैज्ञानिक सलाह पहुंचाने की योजना भी है।

हमीरपुर में खुलेगा प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज खोलने की घोषणा की है। करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस कॉलेज के

लिए 80 कनाल भूमि चिन्हित की गई है और सरकार ने परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में एलाइड एवं स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। इसके अलावा जिले में 74 एकड़ भूमि पर एम्स स्तर का आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर को प्रदेश की शिक्षा राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 156 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं। इनके शुरू होने के बाद विद्यार्थियों के नामांकन में करीब 24 हजार की बढ़ोतरी हुई है। इन स्कूलों के लिए 80 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार नीति तैयार कर रही है। कॉलेजों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए युक्तिकरण भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई भर्तियों में साक्षात्कार की अनिवार्यता खत्म कर मेरिट आधारित चयन किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है। मरीजों से इसके लिए 30 हजार रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि सरकार 90 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। मेडिकल कॉलेजों में 3 – टेस्ला एमआरआई मशीनें भी स्थापित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने किशाऊ परियोजना पर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया।

एच पी एन एल यू के छात्रों ने घंडल पंचायत के वन क्षेत्र में 50 पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (HPNLU) शिमला के यूथ रेड क्रॉस ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और

एनसीसी वॉलंटियर्स के सहयोग से घंडल पंचायत के वन क्षेत्र में पौधारोपण अभियान चलाया।

विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. (डॉ.) प्रीती सक्सेना के नेतृत्व में आयोजित अभियान में करीब 50 स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इनमें बान और देवदार के पौधे शामिल रहे।

अभियान का उद्देश्य वन क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करना रहा। यूथ रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों और एनसीसी कैडेट्स ने पौधारोपण में उत्साह के साथ भाग लिया।

जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव गौतम, HPNLU के यूथ रेड क्रॉस फैकल्टी कन्वेनर डॉ. रोहित शर्मा तथा छात्र सदस्यों ने अभियान में सहयोग किया। विश्वविद्यालय की कुलपति ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक सेवा की भावना को बढ़ावा मिलता है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मंत्रिमंडल के 1628 फैसलों की समीक्षा

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप – समिति की बैठक हुई। बैठक में मंत्रिमंडल के फैसलों के अमल की समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि 13 जनवरी 2023 से 31 मई 2026 तक मंत्रिमंडल ने 1628 निर्णय लिए हैं। इनमें से अधिकांश फैसले लागू किए जा चुके हैं। बाकी निर्णयों को भी जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए।

मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए लंबित फैसलों को समयबद्ध तरीके से लागू करने को कहा। बैठक में गृह, राजस्व, वित्त, लोक निर्माण, वन, जलशक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और अन्य विभागों से जुड़े निर्णयों की भी समीक्षा की गई।

बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

हमीरपुर को मिली 35 इलेक्ट्रिक बसें, 320 किसान परिवारों को सिंचाई योजनाओं का लाभ

3.05 करोड़ की सिंचाई योजनाएं शुरू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर दौरे के दौरान परिवहन निगम के विभिन्न डिपुओं के लिए 35 इलेक्ट्रिक बसों को

हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार का कहना है कि हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में परिवहन निगम के बेड़े में 297 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कृषि उप-निदेशक कार्यालय परिसर में 8.64 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अत्याधुनिक एसआरटी लैब का उद्घाटन किया। इसके अलावा हमीरपुर डिग्री कॉलेज में 1.50 करोड़ रुपये की सीबीटी लैब और 70 टैबलेट वाली लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया गया। कॉलेज में 9 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले छात्राओं के आवास का शिलान्यास किया गया। जिला पुस्तकालय में किताबी कॉर्नर का भी उद्घाटन हुआ।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण प्रोत्साहन परियोजना चरण-2 के तहत 3.05 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विभिन्न उठाऊ सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें नादौन की बसोल, जसोह और खटरोड़, सुजानपुर की घराट, हमीरपुर की डखोल तथा बड़सर की थौन सिंचाई योजनाएं शामिल हैं।

इन योजनाओं से करीब 320 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। योजनाओं के शुरू होने से किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने के साथ फसल विविधिकरण को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 5 करोड़ रुपये की लागत से सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा में निर्मित हॉस्टल का भी उद्घाटन किया।

इस अवसर पर कृषि मंत्री चन्द्र कुमार, विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार शर्मा, एचआरटीसी उपाध्यक्ष अजय वर्मा सहित विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, कांग्रेस पदाधिकारी, अधिकारी तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

1500 मछुआरों को 52.50 लाख रुपये की सहायता

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने झंडूता दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत बिलासपुर के 1500 मछुआरों को 3500 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से कुल 52.50 लाख रुपये डीबीटी के माध्यम से दिए।

मुख्यमंत्री ने मछुआरा समितियों पर लगाए गए पांच गुना जुर्माने को माफ करने और मछली के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने पर सब्सिडी 70 से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने की घोषणा की। पूरे प्रदेश के मछुआरों के लिए लाइफ जैकेट खरीदने को 50 लाख और लैंडिंग सुविधाओं के लिए 10 लाख रुपये देने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि जलाशयों की मछली पर रॉयल्टी अब 15 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दी गई है। मछली को दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बाजारों तक पहुंचाने के लिए रेफ्जिरेटेड वाहनों पर 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लोगों को गांवों में ही रोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मछुआरों के कल्याण के लिए सरकार आगे भी आवश्यक कदम उठाएगी। इसके अलावा झंडूता की 10 संपर्क सड़कों के लिए 10-10 लाख रुपये और राजकीय महाविद्यालय झंडूता में बीसीए और बीबीए कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की गई।

46 नए अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए 46 नए त्वरित प्रतिक्रिया अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें शिमला को 9, कांगड़ा को 8, मंडी और सोलन को 5-5 तथा अन्य जिलों को आवश्यकता के अनुसार वाहन दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए 65.33 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा 37 और नए अग्निशमन वाहनों की खरीद प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 9.60 करोड़ रुपये की लागत से 22 अग्निशमन वाहन खरीदे गए थे। प्रदेश में नए अग्निशमन केंद्र और चौकियां भी स्थापित की जा रही हैं तथा 754 अग्निशमन कर्मियों के पद भरे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक वाहन, उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारियों के माध्यम से आग और अन्य आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य को और तेज किया जाएगा।

एम्स बिलासपुर के विस्तार में पूरा सहयोग देगी सरकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार एम्स बिलासपुर के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में पूरा सहयोग करेगी। सरकार का लक्ष्य एम्स को उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थान बनाना है, ताकि प्रदेश के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके।

मुख्यमंत्री ने एम्स का दौरा कर चिकित्सकों से स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में डायग्नोस्टिक सेवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। आईजीएमसी शिमला और एआईएमएसएस चमियाना में 3-टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की गई हैं, जबकि कई अन्य अस्पतालों में 1.5-टेस्ला एमआरआई मशीनें लगाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीजी मेडिकल सीटों में 330 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार जीन थेरेपी और फोटो थेरेपी जैसे आधुनिक उपचार क्षेत्रों में भी काम कर रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण पर जोर

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और आधुनिक मशीनों की खरीद की समीक्षा की गई।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों को घर के नजदीक बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि 15 से 20 वर्ष पुरानी मशीनों और उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और उपकरणों पर सरकार करीब 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

बैठक में पीईटी स्कैन, डिजिटल मैमोग्राफी, आधुनिक एक्स-रे, ईसीजी, कैथ लैब, हाई-एंड इकोकार्डियोग्राफी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और अन्य आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर चर्चा हुई।

मंत्री ने अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद रखने के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा ढांचे को और मजबूत किया जाएगा।

आईटीबीपी और किनफेड के बीच पहाड़ी भेड़ एवं बकरी के मांस की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की मौजूदगी

में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और किन्नौर जिला सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ लिमिटेड (किनफेड) के बीच पहाड़ी भेड़ और बकरी के मांस की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन हुआ।

समझौते के तहत आईटीबीपी के जवानों के लिए स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण मांस की खरीद और आपूर्ति की जाएगी। शुरुआत में सहकारी क्षेत्र आईटीबीपी की करीब 10 प्रतिशत मांस जरूरत पूरी करेगा। इससे स्थानीय सहकारी क्षेत्र को हर साल लगभग 90 लाख रुपये का कारोबार मिलने की उम्मीद है।

भविष्य में आईटीबीपी की पूरी मांस जरूरत सहकारी क्षेत्र के माध्यम से पूरी होने पर यह आर्थिक अवसर करीब 9 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के पशुपालकों को स्थायी बाजार मिलेगा और स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। साथ ही आईटीबीपी और सीमावर्ती समुदायों के बीच संबंध भी मजबूत होंगे।

उन्होंने कहा कि आगे इस व्यवस्था में स्थानीय अंडे, पोल्ट्री, ताजी सब्जियां, ट्राउट मछली और अन्य उत्पादों को भी शामिल किया जाएगा। इससे स्थानीय उत्पादकों और सहकारी समितियों को रोजगार व कारोबार के नए अवसर मिलेंगे।

द्वारका में हिमाचल निकेतन का काम जल्द पूरा होगा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली के द्वारका स्थित हिमाचल निकेतन का दौरा कर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बाकी फिनिशिंग का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि भवन को जल्द जनता को समर्पित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल निकेतन दिल्ली आने वाले हिमाचलवासियों, खासकर इलाज और पढ़ाई के लिए आने वाले लोगों के लिए सुविधाजनक आवास उपलब्ध करवाएगा। यहां करीब चार सितारा स्तर की सुविधाएं देने की योजना है।

करीब 190 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस भवन में 107 कमरे, रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल, दो बहुउद्देशीय हॉल, बैठक कक्ष और विद्यार्थियों के लिए डॉर्मिटरी होगी। परिसर में पार्किंग, गार्डन और ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने और सभी शेष कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए।

हिमाच्छादित क्षेत्रों में 1 सितंबर से जनगणना

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना-2027 का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। बैठक में प्रशासनिक तैयारियों, तकनीकी व्यवस्थाओं और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की समीक्षा की गई।

निदेशक जनगणना कार्य, हिमाचल प्रदेश दीप शिखा शर्मा ने बताया कि प्रदेश में जनगणना का पहला चरण यानी मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। अब हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनसंख्या गणना का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा।

आम लोगों की सुविधा के लिए 17 अगस्त से 31 अगस्त तक स्व-गणना की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके माध्यम से नागरिक जनगणना पोर्टल पर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

बैठक में अधिकारियों को जनगणना के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल ऐप, मॉनिटरिंग पोर्टल, डिजिटल माध्यमों, वित्तीय नियमों और प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। गणनाकर्मियों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण की भी समीक्षा की गई।

उन्होंने निर्देश दिए कि दूसरे चरण में आंकड़ों की गुणवत्ता और शत-प्रतिशत सटीकता सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि जनगणना के आंकड़े भविष्य की सामाजिक-आर्थिक योजनाओं, नीति निर्धारण और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बजटीय आवंटन के लिए महत्वपूर्ण आधार होते हैं। इसलिए अधिकारियों को इस राष्ट्रीय दायित्व को पूरी गंभीरता, सतर्कता और समयबद्धता के साथ पूरा करना होगा।

आपको मानवता पर भरोसा नहीं खोना चाहिए। मानवता एक महासागर है, अगर महासागर की कुछ बूँदें गंदी हैं, तो महासागर गंदा नहीं हो जाता। .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

वन महोत्सव केवल पौधरोपण का उत्सव न बने

वन महोत्सव हर वर्ष आता है और इसके साथ बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाए जाते हैं। सरकारी विभाग, स्कूल-कॉलेज, पंचायतें, सामाजिक संस्थाएं और आम लोग इसमें भाग लेते हैं। पौधे लगाए जाते हैं, जागरूकता कार्यक्रम होते हैं और सरकारें बड़ी संख्या में पौधे लगाने के आंकड़े जारी करती हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इन पौधों में से कितने पौधे एक, दो या पांच साल बाद भी जीवित रहते हैं? वन महोत्सव की सफलता पौधे लगाने की संख्या से नहीं, बल्कि उनके पेड़ बनने से तय होनी चाहिए।

आज जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। जिससे बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे समय में जंगलों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए जंगलों की रक्षा को आपदा प्रबंधन की नीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई बार पौधरोपण को केवल आंकड़ों की सफलता मान लिया जाता है। एक दिन में हजारों पौधे लगा देना आसान है, लेकिन उन्हें कई वर्षो तक बचाना कठिन काम है। पौधों को पानी चाहिए, सुरक्षा चाहिए और नियमित देखभाल चाहिए। कई स्थानों पर पौधे लगाने के बाद उनकी निगरानी नहीं होती। कुछ पौधे गर्मी में सूख जाते हैं, कुछ पशुओं से नष्ट हो जाते हैं और कुछ बारिश या भूस्खलन में बह जाते हैं। ऐसे में केवल पौधरोपण के आंकड़े पर्यावरण संरक्षण की वास्तविक तस्वीर नहीं बताते।

सरकार को अब पौधे लगाने के साथ उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए। यदि किसी विभाग ने एक हजार पौधे लगाए हैं तो अगले तीन से पांच वर्षो तक यह रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए कि उनमें से कितने जीवित हैं। पौधों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों या संस्थाओं की जिम्मेदारी तय हो। हर वर्ष केवल नए पौधे लगाने के बजाय पुराने पौधों की स्थिति की समीक्षा भी हो। इससे सरकारी योजनाओं की वास्तविक सफलता सामने आएगी।

हिमाचल में पौधरोपण के दौरान स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता देना भी जरूरी है। पौधरोपण की योजना वैज्ञानिक आधार पर तैयार होनी चाहिए, केवल लक्ष्य पूरा करने के लिए नहीं। वन संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। पंचायतों, महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्कूलों को पौधों की देखभाल से जोड़ा जा सकता है। स्कूलों में वन महोत्सव को एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित करने के बजाय पूरे साल की गतिविधि बनाया जा सकता है। प्रत्येक छात्र या समूह को पौधे की जिम्मेदारी दी जाए और उसके विकास का रिकॉर्ड रखा जाए। इससे बच्चों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी। आने वाली पीढ़ी को यह समझना होगा कि पेड़ केवल पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं।

वन महोत्सव का अर्थ केवल पौधे लगाना नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ जंगलों को बचाना, जलस्रोतों को सुरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण तैयार करना होना चाहिए। विकास के नाम पर जंगलों पर बढ़ते दबाव के बीच यह संतुलन बनाना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। सड़क, पर्यटन और अन्य विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन इनके कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने की ठोस व्यवस्था भी होनी चाहिए।

वन महोत्सव वास्तव में तभी सफल होगा जब यह एक दिन के कार्यक्रम से निकलकर पूरे वर्ष की जिम्मेदारी बने। हर साल पौधे लगाने की संख्या बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि पहले लगाए गए पौधों को बचाया जाए। एक पौधा लगाना आसान है, लेकिन उसे पेड़ बनाना कठिन है।

इसलिए अब वन महोत्सव का लक्ष्य केवल 'कितने पौधे लगाए गए' नहीं, बल्कि 'कितने पौधे बचाए गए और कितने पेड़ बने' होना चाहिए। पेड़ आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी, हवा और सुरक्षित पर्यावरण की गारंटी हैं। यदि आज जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी कल पहाड़, जलस्रोत और मानव जीवन सुरक्षित रह पाएंगे। यही वन महोत्सव की वास्तविक भावना और सबसे बड़ी जरूरत है।

इस्लामी आउटरीच, डिजिटल मीडिया और मुस्लिम युवाओं के सामने कट्टरपंथ की चुनौती

गौतम चौधरी

धर्म मनुष्य को जोड़ता है। यह आपस के समन्वय का सबसे शक्तिशाली मानवीय व्यवस्थाओं में से एक रहा है लेकिन जब धर्म तक पहुंचने का माध्यम बदलता है, तो उसके प्रभाव भी बदल जाते हैं। कभी धार्मिक ज्ञान परिवार, शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, मस्जिद, मंदिर, पुस्तक और विद्वानों के माध्यम से धीरे-धीरे व्यक्ति तक पहुंचता था। आज वही ज्ञान कुछ सेकंड की रील, वायरल वीडियो, व्हाट्सऐप संदेश, टेलीग्राम चौनल और सोशल मीडिया एल्गोरिद्म के रास्ते लाखों युवाओं तक पहुंच रहा है।

इस बदलाव को केवल तकनीकी परिवर्तन मानना भूल होगी। सवाल यह है, ''जब धार्मिक शिक्षा का मध्यस्थ शिक्षक और पुस्तक से हटकर एल्गोरिद्म बन जाए, तब धार्मिक चेतना का स्वरूप क्या होगा?''

समस्या सोशल मीडिया पर धर्म की मौजूदगी नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब धर्म का गहरा, ऐतिहासिक और नैतिक विमर्श कुछ उत्तेजक वाक्यों, अधूरे संदर्भो और भावनात्मक वीडियो में सिमटने लगता है। धार्मिक ज्ञान की जगह धार्मिक प्रतिक्रिया लेने लगती है और संवाद की जगह डिजिटल उत्तेजना।

यही वह बिंदु है, जहां मुस्लिम युवाओं के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी होती है। हालांकि यह समस्या आज सभी समाज में व्याप्त है लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव इस्लाम पर ही पड़ता दिख रहा है।

सोशल मीडिया का अपना एक व्यावसायिक तर्क है। जिस सामग्री पर अधिक क्लिक, लाइक, कमेंट और शेयर मिलते हैं, एल्गोरिद्म उसे और अधिक लोगों तक पहुंचाता है। इस व्यवस्था में शांत, जटिल और संदर्भपूर्ण व्याख्या की तुलना में उत्तेजक और भावनात्मक सामग्री को स्वाभाविक बढ़त मिल सकती है।

धर्म स्वभावत: जटिल है। उसमें दर्शन है, नैतिकता है, कानून है, इतिहास है, आध्यात्मिकता है और व्याख्या की लंबी परंपरा है लेकिन डिजिटल माध्यम अक्सर इस जटिलता को कुछ सेकंड के निष्कर्ष में बदल देता है-यह सही है, वह गलत है(यह अपना है, वह पराया है(यह ईमान है, वह कुफ्र है।

यहीं धार्मिक आस्था और कट्टर मानसिकता के बीच की दूरी कम होने लगती है। तकफीर-अर्थात किसी दूसरे मुसलमान को काफिर घोषित करने की प्रवृत्ति, इस खतरे का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। इस्लामी इतिहास में खारिजियों का प्रसंग यह बताता है कि जब कोई समूह अपने धार्मिक सत्य को अंतिम मानकर दूसरों की धार्मिक वैधता ही समाप्त कर देता है, तो मतभेद आसानी से शत्रुता में बदल सकता है।

इतिहास का यह संदर्भ आज के किसी समुदाय या संप्रदाय को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि एक मानसिक प्रवृत्ति के खतरे को समझने के लिए है। कट्टरता का कोई एक चेहरा, एक संप्रदाय या एक राजनीतिक पहचान नहीं होती। उसका मूल आग्रह होता है-''अपने विचार को अंतिम सत्य मानना और असहमति के अधिकार को अस्वीकार करना।''

इस संदर्भ में इस्लामी परंपरा के भीतर मौजूद प्रतिरोधी नैतिकता को समझना जरूरी है। इमाम अली और इमाम हुसैन की शिक्षाओं तथा कर्बला की स्मृति को यदि केवल राजनीतिक संघर्ष या सांप्रदायिक पहचान तक सीमित कर दिया जाए, तो उसके नैतिक संदेश का बड़ा हिस्सा खो जाता है।

कर्बला का संदेश अन्याय के सामने नैतिक साहस का है लेकिन नैतिक साहस और हिंसक उन्माद एक-दूसरे के पर्याय नहीं हैं। यदि कर्बला की स्मृति युवा मन में न्याय, आत्मसम्मान, सत्य, संयम और अन्याय के प्रतिरोध की चेतना पैदा करती है तो वह समाज को मजबूत करती है। वहीं दूसरी ओर, यदि उसी स्मृति को वर्तमान के किसी समुदाय के प्रति घृणा या हिंसा को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इतिहास की नैतिक शक्ति को ही उलट दिया जाता है।

धार्मिक प्रतीकों की भावनात्मक शक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, उस शक्ति को किस दिशा में ले जाया जा रहा है-न्याय और आत्मसंयम की ओर या घृणा व प्रतिशोध की ओर।

यहां मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं और विद्वानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है। यदि युवा सोशल मीडिया पर है तो धार्मिक संवाद भी वहीं होना चाहिए। यह मान लेना कि नई पीढ़ी केवल मस्जिद, मदरसे या पारंपरिक संस्थाओं के माध्यम से धार्मिक ज्ञान हासिल करेगी, अब पर्याप्त नहीं है।

इधर डिजिटल आउटरीच का अर्थ केवल पुराने भाषणों को इंटरनेट पर डाल देना भी नहीं है। आज आवश्यकता ऐसे धार्मिक संचार की है जो युवाओं की भाषा समझे, उनके सवाल सुने और उनके संदेहों का उत्तर दे। ऐसा संवाद जो विज्ञान और आधुनिकता से भागे नहीं, धार्मिक मतभेदों को समझाए, दूसरे धर्मो के प्रति सम्मान पैदा करे और असहमति तथा नफरत के बीच की बुनियादी रेखा स्पष्ट करे।

धार्मिक विद्वान की भूमिका केवल 'सही उत्तर' देने की नहीं हो सकती। उसे युवा को सवाल पूछने की संस्कृति भी देनी होगी। क्योंकि जिस युवा को सवाल पूछने से रोका जाएगा, वह उत्तर कहीं और खोजेगा और डिजिटल दुनिया में उसे उत्तर देने वालों की कोई कमी नहीं है।

कट्टरता से मुकाबला केवल सरकार, पुलिस या गुप्तचर संस्थाओं का काम नहीं हो सकता। परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई युवा किसी उत्तेजक धार्मिक या राजनीतिक सामग्री से प्रभावित होता दिखाई दे तो पहला कदम संवाद होना चाहिए, तत्काल सामाजिक बहिष्कार या अपराधीकरण नहीं। संवाद के दरवाजे बंद होते हैं तो कट्टर विचारों की स्वीकार्यता बढ़ने लगती है।

युवाओं को डिजिटल साक्षरता भी सिखानी होगी। उन्हें यह समझना होगा कि वायरल होना सत्य होने का प्रमाण नहीं है। किसी वक्ता का धार्मिक लिबास उसकी विद्वता की गारंटी नहीं है। किसी वीडियो में पवित्र कुरान की आयत या हदीस का उल्लेख होना भी उसकी व्याख्या के सही होने का प्रमाण नहीं है। धार्मिक ज्ञान के साथ स्रोत की जांच, संदर्भ की समझ और आलोचनात्मक विवेक भी जरूरी है।

कट्टरता के विरुद्ध सबसे प्रभावी लड़ाई समुदाय के भीतर से आती है। मुस्लिम समाज के भीतर ऐसे विद्वानों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो धार्मिक आस्था को कमजोर किए बिना कट्टरता का विरोध कर सकें। यह काम किसी बाहरी शक्ति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

यदि हर आलोचना को 'इस्लाम पर हमला' मान लिया जाएगा तो आत्म-सुधार का रास्ता बंद हो जाएगा लेकिन दूसरी ओर यदि हर धार्मिक व्यक्ति को संभावित कट्टरपंथी मान लिया जाएगा तो संवाद का रास्ता भी बंद हो जाएगा। दोनों प्रकार का अतिवाद खतरनाक हैं।

इसलिए आवश्यकता धर्म के विरुद्ध अभियान की नहीं, बल्कि धार्मिक व्याख्याओं की विवेकपूर्ण समीक्षा की है। आस्था का सम्मान और विचार की आलोचनात्मक जांच एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

इस मामले में राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए? नि:संदेह राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन हिंसा के लिए उकसावे, चरमपंथी प्रचार और आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े डिजिटल अभियानों के खिलाफ कानून का प्रभावी इस्तेमाल होना चाहिए

यहां लोकतांत्रिक सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। कट्टरपंथ से लड़ाई को किसी पूरे धार्मिक समुदाय की निगरानी में बदल देना न केवल नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए खतरा होगा, बल्कि इससे वही अविश्वास पैदा होगा जिसका लाभ कट्टरपंथी प्रचारक उठाते हैं। अपराधी की पहचान उसके कृत्य से होनी चाहिए, उसकी धार्मिक पहचान से नहीं।

सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन इसलिए आवश्यक है क्योंकि आतंकवाद या कट्टरपंथ से लड़ते हुए यदि समाज के किसी बड़े हिस्से में यह भावना पैदा हो जाए कि राज्य उसे संदेह की निगाह से देखता है, तो सामाजिक दूरी बढ़ेगी और संवाद कमजोर होगा। प्रकारांतर में इसका प्रभाव नकारात्मक होगा।

आज मुस्लिम युवाओं के सामने प्रश्न केवल यह नहीं है कि वे क्या पढ़ें। उससे बड़ा प्रश्न यह है कि वे किस पर विश्वास करें। एल्गोरिद्म किसी धर्म का विद्वान नहीं है। वह सत्य और असत्य का निर्णायक भी नहीं है। उसका उद्देश्य उपयोगकर्ता की रुचि और प्रतिक्रिया को अधिकतम करना है। यदि कोई युवा लगातार उत्तेजक धार्मिक सामग्री देखता है, तो डिजिटल व्यवस्था उसे उसी तरह की और सामग्री दिखाती जाती है।

धीरे-धीरे एक ऐसी आभासी दुनिया बन सकती है जिसमें व्यक्ति को लगने लगे कि केवल वही सही सोचता है और बाकी पूरी दुनिया गलत है। यह मानसिकता किसी भी विचारधारा को कट्टर बना सकती है। इसलिए समाधान धर्म से दूरी नहीं है। समाधान है-''धर्म को अधिक गहराई से समझना'' है।

कुरान पढ़ना है तो संदर्भ के साथ पढ़ना होगा। हदीस पढ़नी है तो उसकी प्रामाणिकता और व्याख्या को समझना होगा। इतिहास पढ़ना है तो अनेक स्रोतों से पढ़ना होगा और दूसरे धर्म या समुदाय के बारे में राय बनानी है तो उसके बारे में उसी समुदाय के प्रामाणिक विद्वानों और साहित्य को पढ़ना होगा। अज्ञान कट्टरता की जमीन तैयार करता है और ज्ञान उसके सामने सबसे मजबूत दीवार खड़ी करता है।

आज आवश्यकता ऐसे मुस्लिम डिजिटल नेतृत्व की है जो नई पीढ़ी को केवल धार्मिक पहचान का बोध न कराए, बल्कि न्याय, करुणा, विवेक, आत्मसंयम और मानव गरिमा का अर्थ भी समझाए। कर्बला का नैतिक संदेश हो या इस्लामी परंपरा में ज्ञान की प्रतिष्ठा-इन सबको आधुनिक डिजिटल भाषा में युवाओं तक पहुंचाया जा सकता है। बल्कि पहुंचाया जाना चाहिए।

हमारे युग का सवाल यह नहीं है कि युवा मोबाइल पर क्या देख रहा है। सवाल यह है कि ''मोबाइल उसके भीतर कौन-सी दुनिया बना रहा है।'' उस दुनिया का निर्माण केवल एल्गोरिद्म के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि जब दीन की तालीम किताब, शिक्षक और संवाद से हटकर केवल एल्गोरिद्म से मिलने लगे, तब समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती धार्मिक आस्था की रक्षा नहीं, बल्कि ''धार्मिक विवेक की रक्षा'' की होती है।

व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प साकार होने से हर वर्ग के जीवन में आ रहा सुखद बदलाव

सुखविन्द्र सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री
हिमाचल प्रदेश

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को मेरी और प्रदेश सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त का यह पावन दिवस समस्त देशवासियों के लिए एक उल्लास का पर्व है। यह अवसर उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और विभूतियों को स्मरण करने का भी है, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।

देवभूमि हिमाचल को वीरभूमि के रूप में भी जाना जाता है। हमारे प्रदेश के लोगों ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिया है। कम आबादी के बावजूद हमारे प्रदेश के जवान भारी संख्या में सैन्य बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे प्रदेश के वीर नायकों को चार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। देश का पहला परमवीर चक्र भी कांगड़ा जिले के मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। उनके अलावा कैप्टन विक्रम बतरा, मानद कप्तान संजय कुमार और लैटिनेंट कर्नल धानसिंह थापा को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने तीन वर्ष और आठ महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवधि में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास किया है। सत्ता संभालते ही हमने 'व्यवस्था परिवर्तन' का नारा दिया था और इस संकल्प को धारातल पर साकार किया है। हमारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है और उनका जीवन बदल रहा है।

हमारी सरकार ने वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे अमीर राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। आर्थिक संकट की चुनौती को पार करते हुए अब हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। वर्ष 2022-23 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2,14,952 रुपये थी जो 2025-26 में बढ़ाकर 2,83,626 रुपये हो गई है।

प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने और प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए हम हर मंच पर लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में पहली बार अदालत के माध्यम से जीती लड़ाईयों से प्रदेश को अपने हक वापिस मिलने शुरू हुए हैं। कड़छम-वांगतू परियोजना में मुत बिजली के रूप में हमारा हिस्सा 12 से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है जिससे हर साल 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो रही है जबकि पूर्व सरकार ने डेढ़ साल तक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती ही नहीं दी। इसी तरह, वाइल्ड लावर हॉल होटल का मालिकाना हक वापिस मिलने से प्रदेश के खजाने में 450 करोड़ रुपये आए हैं। इस फैसले से प्रदेश को हर साल 20 करोड़ रुपये की आय होगी।

हमारी सरकार ने किशाऊ बांध परियोजना में भी बड़ी सफलता हासिल की है जिसमें बिजली के रूप में हर साल प्रदेश को 100 करोड़ यूनिट बिजली और लगभग 600 करोड़ रुपये की सालाना आमदनी होगी। पिछली भाजपा सरकार ने इस मामले में प्रदेश के हितों के साथ समझौता किया था। अगर मैं इस मामले में सख्त रुख नहीं अपनाता तो राज्य पर 800 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता।

हम शानन विद्युत परियोजना को फिर प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से हिमाचल प्रदेश के लंबित 7200 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए भी लड़ाई जारी है। चंडीगढ़ में प्रदेश के 7.19 प्रतिशत हिस्से के लिए भी हमने आवाज़ उठाई है। मैं प्रदेश के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार कभी भी उनके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी और हम लोगों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे।

हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सभी चोर दरवाजों को बंद करने का प्रयास किया है जहां से प्रदेश की सम्पदा को लूटा जाता रहा। हमारी सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हम साफ नीयत से प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए पूरे समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर, पिछली भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था जिसकी परतें धीरे-धीरे खुल रहीं हैं। हमारी सरकार का साफ संदेश है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

हमने जब सत्ता संभाली तो प्रदेश पर 76 हजार 700 करोड़ रुपये का कर्ज था। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ की देनदारियां भी पिछली भाजपा सरकार छोड़कर गई। हमने प्रदेश के संसाधानों को बढ़ाया और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए। 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 1952 से प्रदेश को मिल रहे 8 से 10 हजार करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान को भी बंद कर दिया लेकिन प्रदेश इस वित्तीय संकट से बाहर आ चुका है और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है।

प्रदेश के इतिहास में पहली बार गाय के दूधा का खरीद मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूधा का मूल्य 71 रुपये प्रति लीटर किया गया है। कांगड़ा जिले के ढगवार में प्रदेश का पहला स्वचालित मिल्क प्लांट 250 करोड़ रुपये की लागत से इस साल दिसम्बर में काम करना शुरू कर देगा जहां प्रति दिन डेढ़ लाख लीटर दूधा की प्रोसेसिंग शुरू होने से हजारों दूधा उत्पादकों को लाभ होगा।

हमारी सरकार ने नए होम-स्टे बनाने के लिए ब्याज पर सब्सिडी योजना आरम्भ की है। नए होम-स्टे और मौजूदा होम-स्टे में सुधार के लिए 5 करोड़ रुपये के निवेश तक शहरी क्षेत्रों में 3 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 4 प्रतिशत तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जा रही है।

प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना शुरू की है। प्राकृतिक खेती से उगाए गेहूं पर समर्थन मूल्य बढ़ाकर 80 रुपये किया है। वहीं, मक्की का समर्थन मूल्य 50 रुपये और कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित कर वहां के जौ को 80 रुपये समर्थन मूल्य दिया है। बड़ा भंगाल को भी हमने प्राकृतिक पंचायत का दर्जा दिया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है।

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के चौथे चरण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाएं बढ़ाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर 30 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक बसों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इससे लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

हम प्रदेश के अति निर्धान लोगों के लिए अपना परिवार-सुखी परिवार योजना शुरू करने जा रहे हैं। हमने अति गरीब परिवारों का चयन करवाया जिसमें 85 हजार परिवार ऐसे निकले जो कभी बीपीएल में आए ही नहीं और न ही किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है। अब तक 1.80 लाख अति निर्धान परिवार चिन्हित किए गए हैं जिनमें 2.50 लाख महिलाओं की आयु 21 वर्ष से अधिक है। हम इन सभी महिलाओं को इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1500 रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि देंगे, चाहे एक परिवार में तीन पात्र महिलाएं भी क्यों न हों। इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुत बिजली और जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद भी दी जाएगी।

मछुआरों के लिए जलाशयों में मछली पर रॉयल्टी को घटाकर एक प्रतिशत किया गया है। मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू कर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को हर साल 3,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी रही है।

हमारा राज्य देश की पहली बागवानी नीति लागू करने जा रहा है, जिससे लगभग 82,200 लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है। सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन ज़रूरी बनाए जाने से हज़ारों बागवानों को बेहतर दाम मिलने शुरू हुए हैं और उनका शोषण बंद हुआ है।

सेब उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए शिमला जिला में पराला और ढली मंडी, धार्मशाला की पासू मंडी जैसे प्रमुख परिसरों का विकास किया जा रहा है। सेब उत्पादकों को लाभ देने के लिए छैला-नेरीपुल-यशवंतनगर-कुमारहट्टी सड़क के सुधाार के लिए 203.52 करोड़ 52 लाख रुपये और टिक्कर-जरोल-गाहन-ननखड़ी-खमाडी सड़क को स्तरोन्नत करने के लिए 35 करोड़ 93 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार इस क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन कर रही है जिसके कारण प्रदेश ने शत-प्रतिशत साक्षरता हासिल की है। हमारे प्रयासों से प्रदेश आज गुणात्मक शिक्षा के मामले में देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है जबकि 2021 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य 21वें स्थान पर था। प्रदेश में पहली बार अच्छी शिक्षा के लिए घर के नजदीक सीबीएसई स्कूल शुरू करने की पहल की गई है। प्रदेश के 156 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू किया गया है जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। अब तक 24 हज़ार से अधिक बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सीबीएसई स्कूलों में दाखिला लिया है। इन स्कूलों में प्रदेश सरकार केवल 2 हज़ार रुपये फीस ले रही है जबकि प्राइवेट स्कूलों में 50 हज़ार रुपये से अधिक फीस वसूली जाती है।

हमने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की है ताकि इनमें पढ़ने वाले बच्चे भी भविष्य की चुनौतियों से निपटने के काबिल बन सकें। हमीरपुर में प्रदेश का पहला साईंस कॉलेज और अलाइड एण्ड हेल्थकेयर कॉलेज भी खोला जाएगा।

हमारी सरकार ने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत देश-विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान किया है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवारिक आय सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये की गई है।

प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चे विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजे जा रहे हैं। 200 शिक्षकों को भी एक्पोज़र विजिट पर विदेश भेजा गया ताकि दुनिया की श्रेष्ठ प्रणालियां हिमाचल में लागू की जा सकें।

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत विधावाओं और विकलांग माता-पिता के 18 वर्ष तक की आयु के पात्र बच्चों को एक हज़ार रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं। 18 से 27 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रदेश और बाहरी राज्यों के सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के बाद शिक्षा पर होने वाला खर्च राज्य सरकार उठा रही है। शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 7475 पद भरे गए हैं। जेबीटी के 1700 पद भरे जा रहे हैं। सीबीएसई स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 3000 पदों को भरा है।

मरीजों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं देने और आधुनिक मशीनें उपलब्धा करवाने के लिए हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हुई है। आईजीएमसी शिमला, टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ चमियाना अस्पताल में यह सुविधा आरम्भ की गई है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है। प्राइवेट अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी का खर्च 5 लाख रुपये से ज्यादा आता है जबकि हम प्रदेश में 30 से 80 हज़ार रुपये में यह सुविधा दे रहे हैं। आईजीएमसी शिमला में पैट स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए मरीजों को बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। टांडा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में पैट स्कैन मशीनों की खरीद के लिए टेंडर किए जा चुके हैं।

चमियाना अस्पताल, आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में आधुनिक स्वचालित प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। आधुनिक चिकित्सा मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर लगभग 3 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है। पिछले साढ़े तीन सालों में मेडिकल ऑफिसर्ज के 398 पद भरे हैं और 346 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। स्टाफ नर्सों के 468 पद भरे जा चुके हैं और 200 अन्य पद जल्दी भरे जाएंगे। सहायक स्टाफ नर्सों के 748 पद भरे गए हैं तथा 530 पद भरे जा रहे हैं। पैरा मेडिकल स्टाफ के 326 पद भरे जा चुके हैं और 407 पद भरने की प्रक्रिया चल रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की मज़बूती के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्धा हों, इस सोच के साथ 330 पीजी सीटें बढ़ाने का फैसला किया गया है।

प्रदेश के गरीब परिवारों को बेहतरीन उपचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार नई स्वास्थ्य बीमा नीति ला रही है जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा बहुत ही कम प्रीमियम पर उपलब्ध होगी।

नए जंगल तैयार करने, मौजूदा वनों को बचाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हम विशेष कदम उठा रहे हैं। हमने 'मिशन 32 प्रतिशत' की शुरुआत कर वर्ष 2030 तक राज्य के वन क्षेत्र को 29.5 प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जंगल लगाने और जंगल बचाने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत पौधो लगाने और देखभाल करने वाले महिला मॉडलों और युवक मॉडलों को 1.20 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

सुशासन की दिशा में हमने प्रदेश में पहली बार तहसील और उप-तहसील स्तर पर विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर लोगों के कई सालों से लंबित मामलों का निपटारा किया है। इंतकाल के 5.44 लाख, तकसीम के 36,870, निशानदेही के 63 हज़ार और दुरुस्ती के 19,890 मामलों का समाधान किया जा चुका है।

'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सरकार गांवों की समस्याओं को करीब से समझने और उनका समाधाान करने के लिए गांवों तक पहुंच रही है। मैंने खुद प्रदेश के दुर्गम इलाकों जैसे बड़ा भंगाल, डोडरा क्वार, कुपवी, बागा-सराहन और सरची जैसे क्षेत्रों में रात्रि प्रवास किया। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी गांव-गांव जाकर लोगों से सीधो संवाद कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे सुझावों और उनकी समस्याओं को हमारी सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं का आधाार बना रही है।

पिछले तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99 हज़ार 799 नए मामले मंज़ूर किए गए हैं। 1050 से 1100 रुपये तक की मासिक पेंशन प्राप्त कर रहीं 59 वर्ष तक की 2.67 लाख महिलाओं को अब हर महीने 1,500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। सौ प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1700 रुपये से बढ़ाकर 3 हज़ार रुपये प्रतिमाह की गई है।

समाज के सबसे संवेदनशील और वंचित वर्गों, विशेषकर बेसहारा बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरम्भ की गई है। इसके लिए देश का पहला कानून हमारी सरकार ने बनाया है। इसके अंतर्गत 27 वर्ष तक के 6 हज़ार बेसहारा बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ दि स्टेट' के रूप में अपनाया गया है। इन बच्चों की शिक्षा और देखभाल का पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठा रही है। अपना स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए उन्हें दो लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को देश के विभिन्न स्थानों पर एक्सपोज़र विजिट पर भी भेजा जा रहा है ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

पर्यटन हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए प्रदेश की आमदनी बढ़ाने और लोगों को रोज़गार के अवसर देने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। कांगड़ा ज़िला को हिमाचल की पर्यटन राजधाानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके लिए प्रभावित लोगों को 2400 करोड़ रुपये का उचित मुआवजा दिया गया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंडी जिले में माता बगलामुखी रोपवे लोगों को समर्पित किया गया है जबकि चिंतपूर्णी मंदिर

शेष पृष्ठ 6 पर........

बड़सर से मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं, कर्मचारियों–पेंशनरों से लेकर गरीब परिवारों तक को राहत

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश का 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह को हमीरपुर जिले के बड़सर में राज्य स्तर पर मनाया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में पुलिस, होमगार्ड, यातायात पुलिस और विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों ने मार्चपास्ट में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों, पेंशनरों, युवाओं, महिलाओं, बच्चों, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बकाया वेतन के लिए इसी महीने अतिरिक्त 20 हजार रुपये देने की घोषणा की। वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया का 35 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बकाया राशि का 15 प्रतिशत मिलेगा। सरकार इन भुगतानों पर कुल 281 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मल्टी-टास्क वर्कर्स और आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दों पर भी सरकार की ओर से गंभीरता से विचार करने और उचित नीति बनाने की बात कही।

सरकार ने जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरने की घोषणा की है। इससे विभाग में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और खाली पदों को भरने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रही करीब 9,000 आशा कार्यकर्ताओं के मासिक प्रोत्साहन को 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा एनएचएम के उन कर्मचारियों को, जिन्होंने वेतन युक्तिकरण के बाद सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, 1 अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन मिलेगा।

आउटसोर्स स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों, ऑपरेशन थिएटर सहायकों और प्रयोगशाला तकनीशियनों का संशोधित पारिश्रमिक 25 हजार रुपये प्रतिमाह होगा। डेटा एंट्री ऑपरेटरों को 18 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा। यह संशोधित पारिश्रमिक 1 सितंबर 2026 से लागू होगा।

मुख्यमंत्री ने अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने की घोषणा भी की। सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को बेहतर अवसर देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पहली बार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा गया है। इसके अलावा 200 शिक्षकों को भी विदेश भेजकर वहां की बेहतर शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन करवाया गया है।

महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार 'इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना' शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में हिमाचल में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार सामने आया है, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है।

इस योजना का पायलट चरण 2 अक्तूबर से प्रदेश के 21 आईसीडीएस ब्लॉकों में शुरू होगा। छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद परिणामों के आधार पर योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

योजना में माताओं, महिलाओं और 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चों को दिए जाने वाले पोषण सहयोग को बेहतर किया जाएगा। चावल, दाल, तेल, बिस्किट, पंजीरी और मिल्क पाउडर की जगह अधिक पौष्टिक और स्वच्छ तरीके से पैक किए गए प्रीमिक्स खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे। लाभार्थियों की पसंद के अनुसार सप्ताह में तीन बार दूध या अंडे भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पके भोजन की पोषण गुणवत्ता भी बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना शुरू करने की घोषणा की। सरकार के सर्वेक्षण में प्रदेश में करीब 1.80 लाख ऐसे परिवार मिले हैं जिन्हें अधिक सरकारी सहायता की जरूरत है।

यह योजना 2 अक्तूबर से शुरू होगी। अगले दो वर्षों में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्तों को अगले दो महीने में प्रत्येक परिवार की जरूरत का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ इन परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि बीपीएल परिवारों को मिलने वाले मौजूदा लाभ कम नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बीपीएल सूची घटाने की चर्चाओं को गलत बताया और कहा कि सूची में शामिल परिवारों के लाभ जारी रहेंगे।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार डेयरी क्षेत्र पर भी जोर दे रही है। कांगड़ा जिले के ढगवार में करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर क्षमता वाला आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र बनाया जा रहा है। इसका काम इसी वर्ष पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है। इससे कांगड़ा, ऊना, चंबा और हमीरपुर के हजारों किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने अगले दो वर्षों में सोलन, ऊना, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर में दुग्ध प्रसंस्करण ढांचे पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की। इससे डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्रे ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां अलग बागवानी नीति लागू की जाएगी। सरकार के अनुसार इससे करीब 82,200 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

सेब की पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य करने का भी उल्लेख किया गया। सरकार का कहना है कि इससे बागवानों को उनकी फसल के बेहतर दाम मिलने और बाजार में शोषण रोकने में मदद मिली है।

मुख्यमंत्री ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी अपनी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग के बाद हिमाचल को मिलने वाला करीब 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान बंद हुआ है। इसके बावजूद सरकार वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल के भाखड़ा परियोजना से जुड़े करीब 7,000 करोड़ रुपये के दावे को सरकार आगे बढ़ा रही है। शानन, बैरास्यूल, जल उपकर और चंडीगढ़ से जुड़े मामलों में भी प्रदेश के अधिकारों की पैरवी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। 'चिट्टा-मुक्त हिमाचल अभियान' का दूसरा चरण 7 सितंबर 2026 से ऊना में शुरू किया जाएगा। युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए 'खेलो हिमाचल, चिट्टा-मुक्त अभियान' भी शुरू करने की बात कही गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की व्यापक योजना लागू की जा रही है। इसके तहत पुराने जल ढांचे को मजबूत करने, उसका पुनर्निर्माण करने और भूजल स्तर बढ़ाने पर काम किया जाएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और चमियाणा अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है। इससे लोगों को प्रदेश के भीतर ही आधुनिक उपचार मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार निजी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की लागत आम तौर पर 5 लाख रुपये से अधिक होती है, जबकि सरकारी संस्थानों में यह सुविधा 30 हजार से 80 हजार रुपये की लागत में उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को आधुनिक उपचार कम खर्च में मिल सकेगा।

स्वतंत्रता दिवस समारोह पर बडसर में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत देने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, किसान और डेयरी क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं कीं। सरकार ने इन योजनाओं के जरिए कमजोर परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने और प्रदेश में रोजगार तथा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया है।

मुख्यमंत्री ने 4,967 लाभार्थियों को बांटी 20.61 करोड़ की सहायता

शिमला/शैल। बड़सर में आयोजित 80वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता

दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 4,967 लाभार्थियों को 20.61 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित की।

विवाह सहायता योजना के तहत 1,758 लाभार्थियों को 8.98 करोड़ रुपये और शिक्षा सहायता योजना में 2,788 लाभार्थियों को 7.89 करोड़ रुपये दिए गए। मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता के तहत 60 लोगों को 1.49 करोड़ रुपये मिले। इसके अलावा आवास निर्माण, मातृत्व-पितृत्व, दिव्यांग, चिकित्सा और अन्य योजनाओं के तहत भी पात्र लोगों को आर्थिक सहायता दी गई।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 77 वर्षीय सेवानिवृत्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेन्द्र कंवर को सम्मानित किया। डॉ. कंवर ने 80 करोड़ रुपये से अधिक की अपनी चल-अचल संपत्ति डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर को दान की है।

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए और 'वो रुका नहीं' गीत का लोकार्पण भी किया।

व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प साकार

......पृष्ठ 5 का शेष

और बाबा बालकनाथ मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण कार्य जारी है। प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों के साथ-साथ कुल 16 हेलीपोर्ट का निर्माण और विकास कार्य प्रगति पर है।

राज्य सरकार ने आय में वृद्धि और युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए औद्योगिक विकास को प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए हम जल्दी ही अपनी नई उद्योग नीति ला रहे हैं। नई नीति में उद्योगों को प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। जलविद्युत क्षेत्र में छोटी परियोजनाओं को विकसित करने, सौर ऊर्जा परियोजनाओं और गैर-परम्परागत ऊर्जा आधारित निवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने ग्रीन पंचायत कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें सभी पंचायतों में 500 किलोवाट की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं से होने वाली आय का 25 प्रतिशत हिस्सा संबंधित ग्राम पंचायत के अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा।

राज्य सरकार हर नागरिक को साफ पानी उपलब्धा करवाने के लिए काम कर रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में साफ पानी की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की जा रही है। मौजूदा जल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, उसका पुनर्निर्माण करने और भूजल को रिचार्ज करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं।

हम बस यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। हमारे कदम ई-वाहनों की दिशा में बढ़े हैं। प्रदेश में ई-बसों की संख्या बढ़कर 507 हो चुकी है। हम परिवहन निगम के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक और हाईड्रोजन बसों में बदलने पर काम कर रहे हैं।

प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें मिलने वाली अनुग्रह राशि में बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई है। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की है।

वन मित्रों के 2061 पद भरे गए हैं। मंत्रिमंडल की हाल ही में विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 7,500 पद भरने को मंजूरी दी है। पुलिस विभाग में 1088 कांस्टेबलों की भर्ती की गई है। कांस्टेबल के 734 और पद भरे जाएंगे जिसके लिए उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट मिलेगी। सभी पंचायतों में मल्टी टास्क वर्कर के 400 पद, शिक्षा विभाग में जूनियर आफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 200 पद, जिला परिषदों के अधीन ग्राम पंचायतों के लिए जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट के 280 पद भरे जाएंगे। 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार तथा एक-एक मल्टी टास्क वर्कर सहित 3,950 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।

प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का बहुमूल्य योगदान है और हमारी सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमने एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस दी और अन्य लाभ भी दिए जा रहे हैं।

युवाओं में नशे के बढ़ते प्रचलन पर अंकुश लगाने के लिए जन सहयोग से हमारी सरकार ने 'चिट्टा-मुक्त हिमाचल अभियान' शुरू किया है। जल्द ही 'खेलो हिमाचल चिट्टा-मुक्त अभियान' शुरू किया जाएगा जिसके माध्यम से युवाओं को खेलों और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। हमने चिट्टा माफिया की पंचायत स्तर तक मैपिंग की है। हमने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम लागू कर 205 ड्रग माफिया को हिरासत में लिया है। 400 मामलों में नशा माफिया की वित्तीय जांच की जा रही है। नशे की काली कमाई से अर्जित 20 सम्पत्तियों को गिराया गया है।

मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशाओं और अपेक्षाओं के मुताबिक हमारी सरकार राज्य के हरेक क्षेत्र के विकास और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

अंत में, मैं एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं तथा समस्त प्रदेशवासियों के सुखमय और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।

जय हिंद, जय हिमाचल।

सभी प्रदेशवासियों को

स्वतंत्रता दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं

स्वतंत्रता दिवस राष्ट्र के गौरव, स्वाभिमान और अमर बलिदानों के स्मरण का प्रेरणादायी पर्व है। हम अपने महापुरुषों से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लेकर प्रदेश के विकास, समृद्धि एवं खुशहाली के लिए मिलकर कार्य करें तथा हिमाचल के हित को सर्वोपरि रखें।

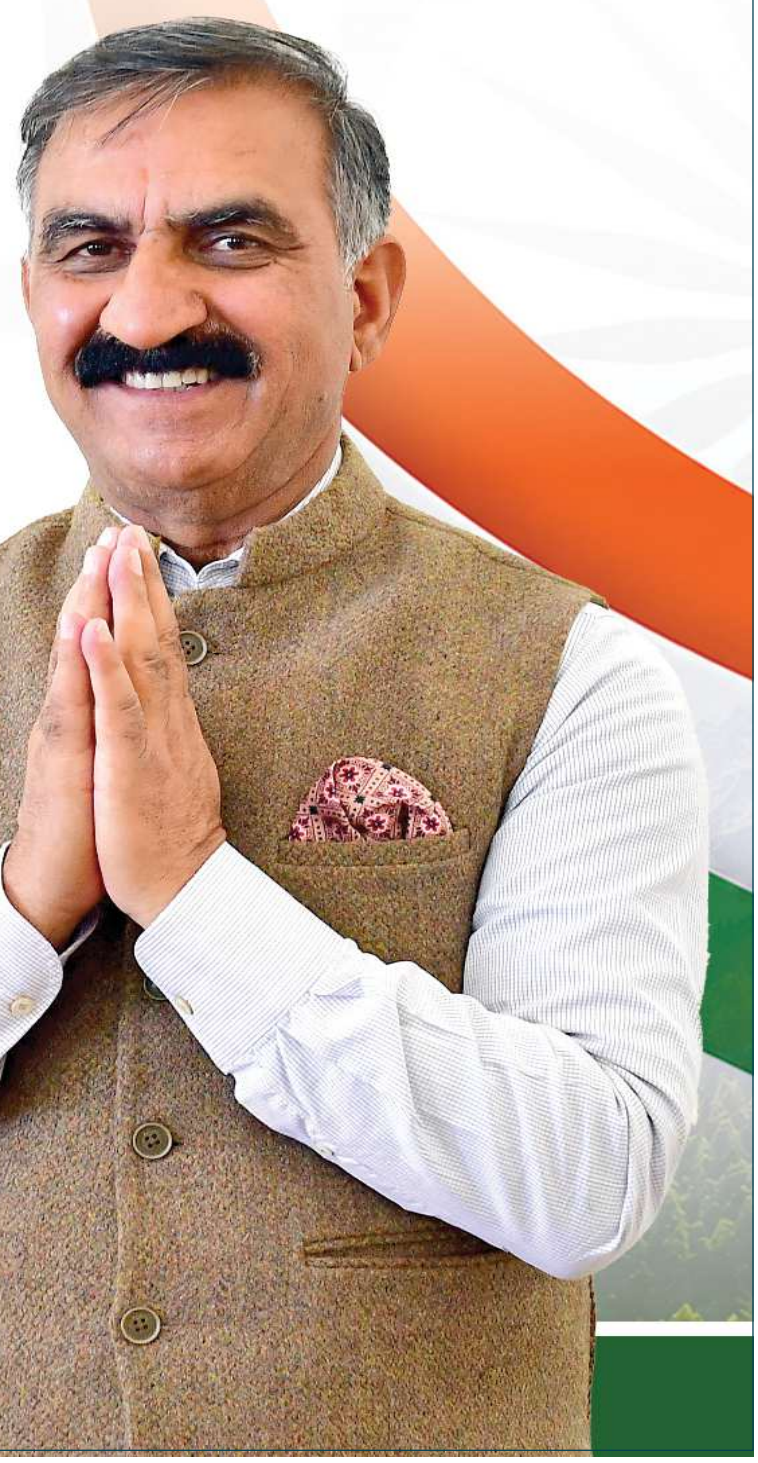

जय हिंद, जय हिमाचल

सुखविन्द्र सिंह सुक्खू

मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

संसद में सवालों से बचाव और सड़क पर लाठीचार्ज

शिमला/शैल। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। यह सत्र विधायी कामकाज से ज्यादा हंगामे, विरोध और सरकार–विपक्ष के बीच टकराव का रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश के गंभीर मुद्दों पर संसद में खुलकर चर्चा नहीं हो सकती, तो आखिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था की उपयोगिता क्या रह जाती है?

मानसून सत्र की शुरुआत ही छात्रों के आंदोलन से जुड़े विवाद के साथ हुई। 20 जुलाई को जंतर–मंतर से संसद की ओर मार्च कर रहे छात्रों और युवाओं पर पुलिस कारवाई हुई। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं और युवाओं से जुड़े सवालों को लेकर संसद तक मार्च का आहवान किया था। पुलिस ने बैरिकेडिंग की और मार्च को रोकने के लिए लाठीचार्ज तथा आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबरें सामने आई।

यहां से एक बड़ा सवाल पैदा हुआ। अगर देश के युवा अपनी समस्याएं लेकर संसद तक पहुंचना चाहते हैं और वहां उन्हें रोक दिया जाता है, तो उनकी आवाज आखिर कहां सुनी जाएगी? सड़क पर आंदोलन करने वालों पर कारवाई हो सकती है, लेकिन संसद तो वह जगह है जहां जनता के सवालों का जवाब सरकार को देना होता है।

छात्र आंदोलन का मुद्दा संसद में उठा। विपक्ष लगातार पुलिस कारवाई और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग करता रहा। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की गई। विपक्ष का आरोप था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे सत्र के दौरान सदन से नदारद रहे। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री 20 जुलाई को सत्र की शुरुआत के अवसर पर और 13 अगस्त को अंतिम दिन लोकसभा में मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह की स्थिति इससे भी अधिक राजनीतिक विवाद का विषय बनी। विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री 13 अगस्त को पहली बार इस मानसून सत्र में लोकसभा पहुंचे, यानी सत्र के 18 दिन बीत जाने के बाद सदन में पहुंचे। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि वह सत्र की शुरुआत से ही नियमित रूप से संसद आ रहे थे। विपक्ष लगातार उनसे 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्यवाही और कथित बल प्रयोग को लेकर जवाब मांगता रहा। अमित शाह ने 12 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि वे छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए सदन में मौजूद रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यह प्रस्ताव पहले क्यों नहीं आया? यदि सरकार को विश्वास था कि गृह मंत्री हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं तो विपक्ष की लगातार मांग के बीच इस मुद्दे पर शुरुआती दिनों में ही चर्चा क्यों नहीं कराई गई? अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दानों सदन में मौजूद रहे, लेकिन उस दिन भी चर्चा नहीं हो सकी।

सबसे गंभीर सवाल संसद के कामकाज को लेकर है। सरकार कह रही है कि विधायी कामकाज हुआ और कई विधेयक पारित हुए। लेकिन सवाल यह है कि विधेयक कितनी गंभीर चर्चा के बाद पारित हुए? उपलब्ध रिपोर्टो के अनुसार मानसून सत्र में 12 विधेयक पारित हुए, जबकि लोकसभा में कामकाज केवल करीब 19 प्रतिशत और राज्यसभा का करीब 39 प्रतिशत रहा।

इस पूरे सत्र की सबसे बड़ी चिंता यह है कि एक तरफ विधेयक पारित हो रहे हैं, दूसरी तरफ सदन का बहुत कम समय काम कर रहा है। यदि संसद में विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा नहीं होगी, विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा अवसर नहीं मिलेगा और सरकार से जवाब नहीं मांगा जाएगा, तो कानून बनाने की प्रक्रिया कितनी प्रभावी मानी जाएगी?

संसद केवल विधेयक पास करने की जगह नहीं है। संसद का मूल काम सरकार से सवाल पूछना, नीतियों पर चर्चा करना, जनता की समस्याओं को उठाना और सरकार को जवाबदेह बनाना है। विपक्ष का काम केवल सरकार का विरोध करना भी नहीं है और सरकार का काम केवल बहुमत के आधार पर विधेयक पारित कराना भी नहीं है। लोकतंत्र में दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है कि सदन चले और जनता के मुद्दों पर चर्चा हो।

यहां सरकार और विपक्ष दोनों को अपनी भूमिका पर गंभीरता से विचार करना होगा। विपक्ष को भी यह समझना होगा कि लगातार हंगामा और सदन की कार्यवाही रोकना जनता के हित में नहीं है। वहीं सरकार को भी यह स्वीकार करना होगा कि बहुमत के आधार पर हर महत्वपूर्ण सवाल को चर्चा से बाहर नहीं किया जा सकता। यदि विपक्ष किसी मुद्दे पर जवाब मांग रहा है, तो सरकार को सदन में उसका जवाब देना चाहिए। संसद में बहस की जगह यदि टकराव ले लेता है, तो नुकसान किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि लोकतंत्र का होता है।

आज देश के युवाओं के सामने रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल हैं। किसानों के सामने खेती और आय के सवाल हैं। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और कानून–व्यवस्था जैसे मुद्दे लगातार जनता के सामने हैं। इन सवालों पर संसद में चर्चा नहीं होगी तो फिर कहां होगी?

लोकतंत्र में सड़क का आंदोलन भी जरूरी है, लेकिन सड़क संसद का विकल्प नहीं हो सकती। संसद वह स्थान है जहां आंदोलन से उठे सवालों को नीति और कानून में बदलने की जिम्मेदारी सांसदों की होती है। यदि सड़क पर उठे सवाल संसद तक पहुंचने के बाद भी चर्चा से बाहर रह जाते हैं, तो लोकतंत्र के प्रति लोगों का भरोसा कमजोर होना स्वाभाविक है।

इसलिए अब सवाल केवल यह नहीं है कि मानसून सत्र में कितने विधेयक पारित हुए। असली सवाल यह है कि उन विधेयकों और देश के ज्वलंत मुद्दों पर कितनी गंभीर चर्चा हुई?

अगर संसद में जनता के सवालों पर बहस नहीं होगी, तो सवाल उठेंगे ही। कभी जंतर–मंतर पर, कभी सड़कों पर और कभी गली–मोहल्लों में। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि जनता के सवाल सड़क पर उठने से पहले संसद में सुने जाएं और सड़क पर उठे सवाल संसद में पहुंचने के बाद दबाए नहीं, बल्कि उनका जवाब दिया जाए।

मानसून सत्र ने इसी बुनियादी सवाल को फिर सामने खड़ा कर दिया है जब संसद में सवाल पूछने और जवाब देने का समय ही नहीं बचेगा, तो जनता अपने सवाल आखिर किससे पूछेगी?

राष्ट्रीय मंच से राजनीति कर रहे मुख्यमंत्री:जयराम

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। भाजपा प्रदेश कार्यालय 'दीपकमल' में ध्वजारोहण के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय महत्व के मंचों का इस्तेमाल राजनीतिक बयानबाजी और अपनी छवि चमकाने के लिए कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश के लिए भावनात्मक और ऐतिहासिक दिन है। ऐसे दिन राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप के बजाय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद किया जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम बच्चों को देश की आजादी का इतिहास बताने और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से परिचित करवाने के लिए होते हैं। लेकिन सरकार इन मंचों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के कामों और प्रचार के लिए कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आपदा के दौरान सरकार द्वारा किए गए कार्यो को स्कूलों के कार्यक्रमों में दिखाकर आखिर सरकार क्या संदेश देना चाहती है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनता का इस सरकार से मोहभंग हो चुका है और अब छोटे बच्चों के कार्यक्रमों के जरिए मुख्यमंत्री अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि जनता के दिल में जगह काम करके बनाई जाती है, प्रचार से नहीं। उन्होंने सरकार पर काम करने के बजाय संस्थानों में तालाबंदी और अव्यवस्था बढ़ाने का आरोप लगाया।

जयराम ने कर्मचारियों, पेंशनरों और एचआरटीसी कर्मियों की मांगों को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार केवल आश्वासन दे रही है। पेट्रोल–डीजल पर लगाये गये सेस को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि आर्थिक संकट का बोझ आम जनता पर डाला जा रहा है। ईंधन महंगा होने से परिवहन, माल ढुलाई और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ रहा है।

उन्होंने चुनावी गारंटियों और बजट घोषणाओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई वादे अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाये हैं। बड़सर के स्कूल कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अनुमति का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचना सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्व को राजनीति का मंच बनाने के बजाय सरकार को जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।

2047 तक विकसित भारत

....पृष्ठ 1 का शेष

निकायों को भी पुराने नियम–कायदों से बाहर निकलना होगा। 2047 के लक्ष्य के अनुरूप नीतियां बनाने की जरूरत बताकर उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को विकास की अगली बड़ी शर्त के रूप में पेश किया।

प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ लड़ाई और नक्सलवाद पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने नक्सली हिंसा में सुरक्षाबलों की बड़ी संख्या में हुई मौतों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि नक्सली हिंसा अब अंतिम चरण में है। हालांकि उन्होंने 'दिमागी नक्सल' शब्द का इस्तेमाल कर वैचारिक स्तर पर भी एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है।

कुल मिलाकर, लाल किले का भाषण उपलब्धियों के दावों से ज्यादा भविष्य के बड़े लक्ष्यों की घोषणा का भाषण रहा। 2047 का विकसित भारत अब केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि सरकार की दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक दिशा के रूप में पेश किया गया है। मगर इस लक्ष्य की असली परीक्षा घोषणाओं में नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने, किसानों की आय बढ़ाने, उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने, युवाओं को कौशल देने, ऊर्जा सुरक्षित करने और वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की वास्तविक हिस्सेदारी बढ़ाने में होगी। अगले पांच से सात वर्ष यह तय करेंगे कि 'सप्त धारा' वास्तव में भारत की विकासधारा बनती है या फिर बड़े लक्ष्यों और जमीनी परिणामों के बीच की दूरी बनी रहती है।